पदाधिकारियों पर कार्रवाई

1. श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 27 दिसम्बर, 2010 को प्रकाशित शीर्षक ''ग्रामीण, अधिकारियों से जूझते रहे मंत्री'', क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने कि कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2010 में मनरेगा और इंदिरा आवास योजनाओं में बिहार अत्यंत ही पिछड़ा साबित हुआ है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त अवधि में मनरेगा के तहत 1,58,740 योजनाओं में से 72,758 योजनाओं का ही कार्य पूरा हुआ है बाकी 86,153 योजनाएं आज तक लंबित है;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु 22 अरब रुपये आवंटन के विरुद्ध मात्र 1300 सौ करोड़ ही आजतक खर्च हो पाये हैं;

(4) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसमें लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों पर कबतक कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सेतु की मरम्मती

2. श्री ललित कुमार यादव--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 20 जनवरी, 2011 को प्रकाशित शीर्षक ''गाँधी सेतु पर मंडरा रहा संकट'' को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने कि कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गाँधी सेतु बिहार की राजधानी को उत्तर बिहार से जोड़ती है, की स्थिति जर्जर है;

(2) क्या यह बात सही है कि 4 से 6 इंच तक सेतु का स्पैन ऊपर नीचे हो रहे हैं तथा दोनों लेनों के 184 हिज बेयरिंग में से 117 खराब हो चुके हैं, जिसमें अबतक मात्र 12 ही बदले गये हैं;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त पुल की मरम्मती कार्य 2001 से चल रहे हैं;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गाँधी सेतु को एक साथ मरम्मत करने हेतु कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

किसानों के हित में कार्रवाई

3. श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 6 दिसम्बर, 2010 को प्रकाशित शीर्षक ''बाढ़ में हर साल बह जाती है 175 करोड़ की फसल'' को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने कि कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में 30 वर्षों में पांच हजार 296 करोड़ की फसल की बर्बादी हो चुकी है, जिससे राज्य के कृषकों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है;

(2) यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार किसानों के हित में कौन-सी कार्रवाई कबतक कराने का विचार रखती है और नहीं, तो क्यों ?

पटना:
दिनांक 23 फरवरी, 20011 (ई०)।

गिरीश झा,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान-सभा।

बि०स०मु० (एल०ए०), 116-डी०टी०पी०--450